श्री जलपाल सिंह कश्यप : आज गन्ने के किसान को 6 या 7 रुपए का भाव मिल रहा है जबकि खाद, पानी, बिजली और डीजल आदि सभी के दाम बढ़ गए हैं। उस जमाने में कम से कम ये चीजें तो सस्ती थीं। आज 13 रुपए एक बैलगाड़ी पर लग रहे हैं। . . . (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं एक अनुरोध कर रहा हूं कि हमें हमारे तरीके से हमारी नीतियों और सिद्धान्तों के अनुसार ही काम करने दीजिए। ऐसा अनुकरण करने के लिए कहिए कि जिससे आपके लिए, हमारे लिए और देश के लिए भी पैदा हो जाए। ग्राम पंचायतों में नलकूपों और जलाशयों आदि के संबंध में जो योजना है, वह केन्द्र सरकार से मिलने वाली सहायता के अन्तर्गत ही आती है। उसमें यही कोशिश है कि ग्राम पंचायतों में प्रभावित क्षेत्रों में जलाशय बनाए जा सकें। भुखमरी के संबंध में आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए हम प्रदेश सरकारों से बराबर सम्पर्क बनाए रखते हैं और जो कुछ सहायता करना सम्भव होता है, वह करते हैं। बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या दूसरी प्रदेश सरकारों से जब भी सूचना प्राप्त होती है तो हम ग्राम पंचायतों के स्तर पर या अपने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित कराते हैं कि वहां कुछ न कुछ अनाज रहे जिससे भुखमरी की स्थिति पैदा न होने पाए।

13.55 Hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Connecting Udaipur and Delhi by a Superfast train.

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : श्रीमन्, मैं सदन का ध्यान राजस्थान के कश्मीर प्रदेश उदयपुर की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां से हजारों की संख्या में लोग प्रति सप्ताह, प्रति दिन अहमदाबाद व दिल्ली आते जाते हैं। इस प्रदेश में आवगमन के साधन वैसे ही बहुत कम हैं। तथापि रेल व्यवस्था का बिल्कुल अभाव है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा-डूंगरपुर से भी उदयपुर एवं दिल्ली का मिलाना रेल व्यवस्था से अति आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार सरकार ने अभी जोधपुर से सुपर फास्ट ट्रेनों व दिल्ली से अहमदाबाद को जोड़ा है उसी तरह से उदयपुर को दिल्ली व मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा-डूंगरपुर होते हुए, अहमदाबाद से सुपर फास्ट ट्रनों से शीघ्र जोड़ा जाये।

(ii) Financial Assistauce to Kerala to meet drought situation in the state.

PROF. P.J. KURIEN (Mavelikara) : Kerala is under the grip of a severe and out of 1300 villages in the State 900 have already been declared drought affected by the Government of Kerala. Never before in the history of Kerala has witnessed a drought ot this magnitude. Not only that the prices of rice and other commodities have shot up, but also they are scarcely available in the market. In many villages the situation is so grave that people are not getting even drinking water.

The economy of the State is on the verge of ruin. Adding fuel to fire, the power generation has fallen steeply resulting in loss of revenues to the exchequer and fall in production in the industrial sector. All these have created an unprecedented and very serious situation demanding the immediate attention of the Central Government. If the Central Government do not rush to provide necessary assistance, the consequences will be alarming, as the situation may lead to starvation-death and spreading of epidemics.

In view of the above serious situation, the Kerala Government have asked for a special assistance of Rs. 200 crores from the Centre. This amount itself is too meagre considering the gravity and magnitude of the problem. The Chief Minister of Kerala has also met the Prime Minister and Finance Minister and made representations in this regard.